भारत सरकार
योजना मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2860
दिनांक 18.08.2025 को उत्तर देने के लिए

आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों का औद्योगिक एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण

2860. **श्रीमती संगीता यादव:**

क्या ***योजना*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों को देश की औद्योगिक और डिजिटल अर्थव्यवस्था से एकीकृत करने के लिए कोई रूपरेखा बनाई है या नीतिगत ढांचा विकसित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास, उद्यमिता और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट पहल की गई हैं;

(ग) देश के विकास लक्ष्यों के संदर्भ में इन जिलों और ब्लॉकों की औद्योगिक और डिजिटल प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है; और

(घ) इस परिवर्तन में स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर मौजूद वर्गों की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) औद्योगिक और डिजिटल अर्थव्यवस्था आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों सहित पूरे देश के समग्र विकास का एक अनिवार्य भाग है। देश के दूरस्थ गांवों और द्वीपों में हाई बैंडविड्थ क्षमतावाली इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तथा मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक भी शामिल हैं, जहां वर्तमान में कवरेज का अभाव है। यह कार्य दूरसंचार विभाग (डीओटी) की डिजिटल

भारत निधि (डीबीएन) [पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)] से प्राप्त वित्तपोषण से किया जा रहा है।

कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई कार्यान्वयन के अधीन हैं। प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नप्रकार हैः

i. **भारतनेट परियोजना** को सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। सृजित अवसंरचना एक राष्ट्रीय संपत्ति है और यह सेवा प्रदाताओं को एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) कनेक्शन, लीज़्ड लाइन, डार्क फाइबर, और मोबाइल टावर बैकहॉल आदि जैसी ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध हैं। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत जून 2025 तक कुल 2,14,325 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर लिया गया है।

ii. वंचित दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में **हाईस्पीड इंटरनेट/डेटा और मोबाइल सेवाएं** उपलब्ध कराने के लिए कई लक्षित स्कीमें दूर संचार विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई हैं। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीपों (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप) में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए समग्र दूरसंचार विकास योजनाएं (सीटीडीपी), वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) से बाधित क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, सीमावर्ती गांवों में मोबाइल सेवाओं के लिए स्कीमें और सभी वंचित गांवों को 4जी सैचुरेशन स्कीम के तहत कवर करना शामिल है। कुल 26,316 करोड़ रु. की लागत वाली 4जी सैचुरेशन परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। जून 2025 तक विभिन्न सरकारी वित्तपोषित मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 21,748 मोबाइल टावर चालू किए जा चुके हैं।

iii. चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (2312 कि.मी.) के बीच **सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल** लगाकर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को हाईस्पीड इंटरनेट/डेटा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं ने द्वीप समूह में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाएं, मोबाइल सेवाएं (4जी/5जी), और अन्य हाई-स्पीड डेटा सेवाएं शीघ्र प्रारंभ करने की प्रक्रिया को सुकर बनाया है।

iv. कौशल विकास आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के समग्र निगरानी ढाँचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, आकांक्षी जिलों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क से स्किल,

री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग का प्रशिक्षण और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। आकांक्षी जिलों में प्रशिक्षित व्यक्तियों और स्थापित या संचालित प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है। इसके अलावा, औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीपीआईआईटी (उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) की कुछ योजनाएँ हैं जो कुछ आकांक्षी जिलों को कवर करती हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक -II में संलग्न है।

ग. कौशल विकास और डिजिटल अवसंरचना से संबंधित प्रमुख संकेतकों सहित आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के सभी प्रमुख प्रदर्शन सूचकांकों (केपीआई) की प्रगति की निगरानी चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही है, जिसे https://championsofchange.gov.in/ पर सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है।

घ. स्थानीय समुदायों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सितंबर 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जिला/ब्लॉक स्तर पर चिंतन शिविर और संकल्प सप्ताह का आयोजन किया गया।

*****

अनुलग्नक - I

आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों का औद्योगिक एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को श्रीमती संगीता यादव द्वारा पूछा गया राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं 2860 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

आकांक्षी जिलों में एमएसडीई की उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

पीएमकेवीवाई (2015-16 से 31.05.2025 तक)	जेएसएस (2018-19 से 31.03.2025 तक)	एनएपीएस (2018-19 से 31.05.2025 तक)	आईटीआई (2018 से 2024)
17,45,879	6,08,427	1,81,252	10,13,732

देशभर के आकांक्षी जिलों में स्थापित या संचालित प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण निम्नानुसार है:

पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस प्रतिष्ठान	आईटीआई (सत्र 2023-24)	
			सरकारी आईटीआई	निजी आईटीआई
1,664	71	2,461	422	1,139

अनुलग्नक- II

आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों का औद्योगिक एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को श्रीमती संगीता यादव द्वारा पूछा गया राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं 2860 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीपीआईआईटी की योजनाओं की सूची:

- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी): उत्तराखंड राज्य का उधम सिंह नगर, आंध्र प्रदेश राज्य का कडपा और बिहार राज्य का गया

- पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना (उन्नति): अरुणाचल प्रदेश का नामसाई , असम के बक्सा, बारपेटा, दरांग, धुबरी, गोलपारा, हैलाकांडी और उदलगुरी, मणिपुर का चंदेल, मेघालय का रिभोई, मिजोरम का ममित, सिक्किम का सोरेंग, नागालैंड का किफिरे और त्रिपुरा का धलाई।

- जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना: बारामूला और कुपवाड़ा

- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) 2021 : चंबा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर

- जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) 2021 : बारामूला और कुपवाड़ा।

*****